भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 473
गुरुवार, 28 नवंबर, 2024/7 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानपत्तनों का विकास

473. श्री सेल्वाराज वी.:
श्री सुब्बारायण के.:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने छोटे शहरों में हवाई यात्रा की मांग में अनुमानित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 50 से अधिक विमानपत्तनों के विकास और विस्तार के लिए पांच वर्षीय योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त उद्देश्य के लिए किन शहरों का चयन किया गया है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख): छोटे शहरों में हवाई यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, नागर विमानन मंत्रालय ने देश में विमानन अवसंरचना के विकास के माध्यम से दूरस्थ और क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय संपर्क योजना - उड़े देश का आम नागरिक (आरसीएस - उड़ान) शुरू की है। इस योजना में वैध बोली प्रक्रिया के माध्यम से हवाईअड्डे की पहचान किए जाने और उसके बाद पहचाने गए हवाईअड्डे को जोड़ने वाले मार्गों पर परिचालन के लिए चयनित एयरलाइन प्रचालक (एसएओ) को अवॉर्ड किये जाने पर असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों के पुनरुद्धार/उन्नयन की परिकल्पना की गई है।

भारत सरकार ने एएआई/राज्य सरकार/सीपीएसई/रक्षा मंत्रालय के स्वामित्व वाले असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों/हेलीपोर्टों/वाटर एयरोड्रोमों के पुनरुद्धार/उन्नयन के लिए 4500 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार करने हेतु अतिरिक्त 50 हवाईअड्डों, हेलीपोर्टों, वाटर एयरोड्रोमों और उन्नत लैंडिंग ग्राउंड के पुनरुद्धार के लिए पुनरुद्धार और विकास योजना के चरण - II में 1000 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

दिनांक 25.11.2024 तक, 86 असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों (13 हेलीपोर्टों और 02 वाटर एयरोड्रोमों सहित) को जोड़ने वाले 609 आरसीएस मार्गों को प्रचालनरत किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, अब तक 4134 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है।

*****